छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

षोडश सत्र

बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023

(फाल्गुन 10, शक सम्वत् 1944)

[अंक 01]

Web copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. चरणदास महंत
उपाध्यक्ष	श्री सन्तराम नेताम
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

सभापति तालिका

1. श्री सत्यनारायण शर्मा,
2. श्री धनेन्द्र साहू,
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह,
4. श्री सौरभ सिंह,
5. श्री बघेल लखेश्वर.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

श्री विश्व भूषण हरिचन्दन

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)
03.	श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
04.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री	संसदीय कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट
05.	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री	स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
06.	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री	परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य
07.	श्री कवासी लखमा, मंत्री	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग
08.	डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम
09.	श्री अमरजीत भगत, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
10.	श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण
11.	श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)
12.	श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग
13.	श्री उमेश पटेल, मंत्री	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय सचिवों की सूची

01. श्री चिंतामणी महाराज
02. श्री पारसनाथ राजवाड़े
03. श्रीमती अंबिका सिंहदेव
04. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय
05. श्री द्वारिकाधीश यादव
06. श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे
07. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
08. श्री कुंवर सिंह निषाद
09. डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह
10. श्री रेखचंद जैन
11. सुश्री शकुन्तला साहू
12. श्री शिशुपाल सोरी
13. श्री यू.डी. मिंज
14. श्री विकास उपाध्याय
15. श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर

.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
02.	अमरजीत भगत	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
03.	अरूण वोरा	64-दुर्ग शहर
04.	अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती	47-धरसींवा
05.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)
06.	अंबिका सिंहदेव, श्रीमती	03-बैकुंठपुर
07.	अमितेश शुक्ल	54-राजिम
08.	अनूप नाग	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
09.	आशीष कुमार छाबड़ा	69-बेमेतरा

इ

01.	इंद्रशाह मण्डावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
02.	इंदू बंजारे, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उमेश पटेल	18-खरसिया

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.	32-मस्तूरी (अ.जा.)
03.	किस्मत लाल नंद	39-सरायपाली (अ.जा.)
04.	कुलदीप जुनेजा	50-रायपुर नगर उत्तर
05.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
06.	के.के.ध्रुव, डॉ.	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
07.	केशव प्रसाद चन्द्रा	37-जैजेपुर

ख

01	खेलसाय सिंह	04-प्रेमनगर

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग

01.	गुरू रूद्र कुमार	67-अहिवारा (अ.जा.)
02.	गुरूदयाल सिंह बंजारे	70-नवागढ़ (अ.जा.)
03.	गुलाब कमरो	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

च

01.	चक्रधर सिंह सिदार	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
03.	चंदन कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04.	चंद्रदेव प्रसाद राय	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05.	चिन्तामणी महाराज	08-सामरी (अ.ज.जा.)

छ

01.	छन्नी चंदू साहू, श्रीमती	77-खुज्जी

ज

01.	जयसिंह अग्रवाल	21-कोरबा

ट

01.	टी.एस.सिंहदेव	10-अम्बिकापुर

ड

01.	डमरूधर पुजारी	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

त

01.	ताम्रध्वज साहू	63-दुर्ग ग्रामीण

द

01.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
02.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी
03.	देवती कर्मा	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
05.	देवेंद्र बहादुर सिंह	40-बसना

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध

01.	धरमलाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धनेन्द्र साहू	53-अभनपुर
03.	धर्मजीत सिंह	26-लोरमी

न

01.	ननकीराम कंवर	20-रामपुर (अ.ज.जा.)
02.	नारायण चंदेल	34-जांजगीर-चांपा

प

01.	प्रकाश शक्राजीत नायक	16-रायगढ़
02.	प्रमोद कुमार शर्मा	45-बलौदाबाजार
03.	पारसनाथ राजवाड़े	05- भटगांव
04.	प्रीतम राम, डा.	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
06.	पुरूषोत्तम कंवर	22-कटघोरा
07.	प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बृजमोहन अग्रवाल	51-रायपुर नगर(दक्षिण)
02.	बृहस्पत सिंह	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)

भ

01.	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

म

01.	ममता चंद्राकर, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	मोहन मरकाम	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
03.	मोहित राम	23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.)
03.	मोहम्मद अकबर	72-कवर्धा

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	यू.डी.मिंज	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

र

01.	रजनीश कुमार सिंह	31-बेलतरा
02.	रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती	58-धमतरी
03.	राजमन वेंजाम	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
04.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
05.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
06.	रामपुकार सिंह ठाकुर	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)
07.	रविन्द्र चौबे	68-साजा
08.	रश्मि आशिष सिंह, डॉ. (श्रीमती)	28-तखतपुर
09.	रेखचंद जैन	86-जगदलपुर
10.	रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती)	25-कोटा

ल

01.	लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
03.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
02.	विनय जायसवाल, डॉ.	02-मनेन्द्रगढ़
03.	विनय कुमार भगत	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
04.	विद्यारतन भसीन	66-वैशाली नगर
05.	विकास उपाध्याय	49-रायपुर नगर पश्चिम
06.	विनोद सेवन लाल चंद्राकर	42-महासमुन्द

श

01.	शकुन्तला साहू, सुश्री	44-कसडोल
02.	शिवरतन शर्मा	46-भाटापारा
03.	शिवकुमार डहरिया, डॉ.	52-आरंग (अ.जा.)
04.	शिशुपाल सोरी	81-कांकेर (अ.ज.जा.)
05.	शैलेश पाण्डे	30-बिलासपुर

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स

01.	सत्यनारायण शर्मा	48-रायपुर ग्रामीण
02.	संतराम नेताम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)
03.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
04.	सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
05.	सौरभ सिंह	33-अकलतरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023

(फाल्गुन-10, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>राष्ट्रगीत/राज्यगीत</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" तथा राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" तथा राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- अब सदन माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा ।

(माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई)

समय :

11.06 बजे **(माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ)**

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण की प्रथम कंडिका- 1 एवं अंतिम कंडिका 71 हिंदी में पढ़ेंगे । साथ ही कंडिका-2 से 53 तक अंग्रेजी में पढ़ेंगे तथा अभिभाषण की शेष कंडिकाओं को पढ़ा हुआ माना जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ सरकार के सेक्रेटरी ने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में केस किया है । ये राज्यपाल महोदय के पद को मान्यता देती है कि नहीं देती है और विधानसभा में क्यों बुलाया है ? हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय महामहिम महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार आपके सचिव के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में गयी है । मामला सबज्यूडिशियस है । (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- इस सदन को गुमराह मत करिये । (व्यवधान) माननीय राज्यपाल जी का सम्मान करिये । सदन को गुमराह मत करिये । (व्यवधान)

समय :

11.08 बजे

<u>राज्यपाल का अभिभाषण</u>

माननीय राज्यपाल महोदय (श्री विश्व भूषण हरिचंदन) :- माननीय सदस्यगण, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सोलहवां सत्र, फाल्गुन-चैत्र के पावन माह में आयोजित किया जा रहा है । (व्यवधान) इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं । आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं । (व्यवधान) वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त जनादेश से वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ था ।

श्री अजय चंद्राकर :- मामला सबज्यूडिशियस है । आपके अधिकारों की समीक्षा हो रही है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नये राज्यपाल जी का सम्मान तो करो । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपसे अपना भाषण पढ़वा रही है, आपको मान्यता देती है या नहीं देती है ? ये आपके खिलाफ हाईकोर्ट में गये हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके अधिकारों के खिलाफ हाईकोर्ट में गये हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपसे अपना भाषण पढ़वा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री स्तर का आदमी सचिव स्तर के आदमी पर आरोप लगा रहा है। इतना स्तर गिर गया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल के पद पर आरोप लगाया गया है । (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- बुजुर्ग राज्यपाल जी का यही सम्मान । (व्यवधान)

(कृषि मंत्री) श्री रविन्द्र चौबे :- आपके राज्यपाल का ऐसा सम्मान। बुजुर्ग राज्यपाल जी का यही सम्मान। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :- मेरी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल का यह पांचवां बजट सत्र है। वर्ष 2023-24 के बजट सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श और निर्णय की कार्यवाही आप लोगों द्वारा की जाएगी। 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' तथा 'सेवा-जतन-सरोकार' के ध्येय वाक्य के साथ जो 'छत्तीसगढ़ मॉडल' की शुरूआत हुई थी, उसे मुकाम तक पहुंचाने में मेरी सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने के लिए, मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- एरोप्लेन में वकील आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी गई है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आप इसमें पुनर्विचार करिए। आपके अधिकार क्या है? आपके दायित्व क्या हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- जब आपके अधिकारों को चुनौती दी जा रही है तो इसका अर्थ क्या रह गया है? माननीय राज्यपाल जी, जब अधिकार को ही चुनौती दी जा रही हे तो यह क्या है? आप लोग राज्यपाल महोदय के पद के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। आप राज्यपाल के अधिकार के खिलाफ कोर्ट में गये हैं। आप राज्यपाल के अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में गये हैं या नहीं गये हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- राज्यपाल के अधिकारों के खिलाफ कोर्ट गये हैं?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- उनके विचारों को सुनने दीजिए न। आप क्या हल्ला मचा रखे हो। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय की गरिमा का तो ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने हाईकोर्ट में गये हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्यपाल के दायित्व और अधिकार क्या हैं? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय के विचार का सम्मान करना सीखिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सरकार कोर्ट में राज्यपाल के विरूद्ध चुनौती देने का काम कर रही है। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- आप क्या दिखाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार राज्यपाल पद के विरूद्ध कोर्ट में गयी है तो जिस राज्यपाल के पद के ऊपर सरकार को विश्वास नहीं है, उनसे से अभिभाषण पढ़वा रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

2. The biggest proiority of my government has been the integrated and holistic development due to which farmers and rural families in Chhattisgarh have become increasingly prosperous and happy.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गयी है। पहले कोर्ट का फैसला आ जाये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कोर्ट का फैसला आ जाये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- जब माननीय राज्यपाल के अधिकार को सरकार चुनौती दे रही है तो..।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- ये माननीय राज्यपाल जी छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और सदन को संबोधित कर रहे हैं और आप क्या दिखा रहे हो? आप क्या सिखाना चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल महोदय के खिलाफ केस किया जा रहा है। राज्यपाल और इस सदन के ऊपर सरकार को विश्वास नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये क्या सिखाना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि राज्यपाल वही अभिभाषण पढ़ते हैं जो सरकार की केबिनेट मंत्री पढ़वाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य सरकार को राज्यपाल के ऊपर विश्वास नहीं है, उन राज्यपाल जी से वे अपना अभिभाषण क्यों पढ़वा रहे हैं?

माननीय राज्यपाल महोदय :-

3. My government has accepted the big challenge of freeing soil of our state from toxic chemicals and for it alongwith various efforts it has been decided to celebrate 'Akti Festival' every year as 'Mati Pujan Day'.

4. Through 'Suraji Gaon Yojana', my government has conserved 'Narva Garuva, Ghurva, Bari', encouraged multidimensional development and increased the livelihood opportunities through it.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो गयी है। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- जब विश्वास ही नहीं है तो अभिभाषण क्यों पढ़वा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पहले अधिकार और दायित्व को परिभाषित करिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें अपने राज्यपाल पर भरोसा ही नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय राज्यपाल महोदय आये हैं, उनके विचारों का सम्मान करना तो सीखिए। सुनने दीजिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संकट की स्थिति है। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

5. Over 100 lakh quintals of cow dung have been purchased under 'Godhan Nyay Yojana' and 28 lakh quintals of vermi-compost, super compost and super compost plus have been produced which in itself is a big achievement. The income increased by stockbreeders, Gauthan samitis and self help groups (SHGs) has crossed Rs. 400 crore. The process of setting up 23 paint manufacturing units in 13 districts has started.

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्यपाल महोदय के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार के अभिभाषण को पढ़ने का औचित्य ही क्या है? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- इस सरकार को सोचना चाहिए। यह संवैधानिक संकट की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय यह सरकार कोर्ट में गयी है । संवैधानिक संकट की स्थिति है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इस अभिभाषण को पढ़ने का औचित्य क्या है? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको तो बात ही नहीं सुननी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरी जनता देख रही है। माननीय अहंकार तो रावण का भी टूटा था। आप कौन सी चीज हैं? अहंकार रावण का भी टूटा था। रविन्द्र चौबे का भी अहंकार नहीं चलेगा। बड़े-बड़े आये और चले गये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- बड़े-बड़े आये और चले गये। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- 15 साल में टूटा है। 15 साल का टूटा या नहीं टूटा? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट में गयी है। हम थोड़ी न गये हैं। (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- राज्यपाल के अभिभाषण में आप ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संकट की स्थिति है। सरकार खुद कोर्ट में गयी है और कोर्ट में जाने के बाद में चुनौती दी है। पहले कोर्ट का निर्णय आना चाहिए और उसके बाद में अभिभाषण। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

6. Pasture lands have been developed in 5 thousand 874 Gauthans, where 2 lakh 30 thousand quintasls of green fodder has been produced and has been collected 15 lakh 80 thousand quintals of dry straw fodder.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अपमानित किया गया है। आपके खिलाफ बोला गया है। आपके अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में गये हैं। बड़े-बड़े वकील कराये गये हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय, आपके अधिकारों को चुनौती दी गयी है। ये लोग आपके अधिकारों को चुनौती देकर आपसे अभिभाषण पढ़वा रहे हैं। पहले आपका अधिकार स्पष्ट हो जाये। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

7. This year 23 lakh 50 thousand farmers have cultivated paddy in 30 lakh 14 thousand hectares and sold 1 crore 7 lakh 53 thousand metric ton paddy on minimum support price. This way Chhattisgarh has become the first state to procure paddy from maximum numbers of farmers.

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, वैसे भी यह पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता तो अंग्रेजी समझेगी नहीं। तो आप पहली और आखिरी

लाइन पढ़वा दीजिए और फुर्सत करिए और राज्यपाल जी को भी आराम दीजिए। अंग्रेजी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई समझ ही नहीं रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार को संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भरोसा भी नहीं है। पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिए। (व्यवस्था)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

8. My government has launched 'Chhattisgarh Millet Mission' in year 2022-23. For encouraging tea and coffee farming in the state, 'Chhattisgarh tea-coffee board' has been formed.

श्री धर्मजीत सिंह :- ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। केवल टी.एस.बाबा साहब समझ रहे हैं। वे ईयर फोन लगाये हैं। हम लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? हिन्दी में बोल दीजिए और हिन्दी में नहीं बोलते तो एक-एक लकीर आगे पढ़ दीजिए और फुर्सत करिए। वे अंग्रेजी समझ जायेंगे वे अंग्रेजी मीडियम के हैं। आप नहीं समझेंगे।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत भाई, मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। आप उसमें एडमिशन ले लेते। धर्मजीत भाई इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं ताकि हम सब लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सकें।

श्री धर्मजीत सिंह :- स्कूल खोले हैं तो क्या भर्ती होते ही अंग्रेजी समझने लगेंगे क्या? आप तो ऐसा बता रहे हैं। राज्यपाल जी अंग्रेजी में मत पढ़िए। आप वरिष्ठ हैं। आपका सम्मान है आप थोड़ा अंग्रेजी में मत पढ़िए। पहली और आखिरी लाइन पढ़ दीजिए।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

9. My government started the 'Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana', in Kharif year 2019, under the scheme input subsidy of Rs. 16 thousand 415 crore have been provided.

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत जी, Governor's speech is continue, please listen. (हंसी)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

10. Under the interest-free agricultural loan scheme for the year 2022-23, loans of Rs. 6 thousand 141 crore has been disbursed, which is the highest record so far.

11. Kisan Credit Cards were issued, which has now increased to 21 lakh 23 thousand. The numbers of Bank Mitras have also been doubled to 35,000.

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह मामला था तो यह कोई पुराना मामला है। उसे इस तरीके से हल्ला नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नर का सम्मान करना चाहिए। ये इस तरह से फालतू का हल्ला कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है तो हल्ला नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आप कुछ समझ रहे हो क्या?

माननीय राज्यपाल महोदय :-

12. The state is producing 5 lakh 91 thousand metric ton fish. Chhattisgarh has become the sixth largest state in the country.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे व्यवस्था चाह रहे हैं कि जिस राज्यपाल के पद के ऊपर सरकार को विश्वास नहीं है और उस सरकार का अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, उसका औचित्य क्या है? अगर सरकार राज्यपाल के विरूद्ध हाईकोर्ट गयी है और उनसे वह अभिभाषण पढ़वा रही है तो उसका औचित्य क्या है ? उनके अधिकारों को चुनौती दी गयी है।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

13. Tendu leaf collection remuneration has been increased from Rs. 2500 per standard bag to Rs. 4 thousands per standard bag. Incentive amount of Rs. 340 crores has been given in the past three years. Over 130 products are being processed and sold under the name of 'Chhattisgarh Herbal Brand'.

श्री अमितेश शुक्ल :- पहले का मामला होगा। आपकी सरकार ने बनाया है, हमने बनाया है क्या ? आपकी ही सरकार ने बनाया है और आप ही आब्जेक्शन करते हो। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इनको forcefully तो नहीं लाया गया है। यह भी पता कराओ। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

14. To link livelihood with plantation 'Mukhyamantri Vrisksha Sampada Yojana" has been started Under which commercial tree species will be planted on lands own by private farmer.

श्री कुलदीप जुनेजा :- इंग्लिश वाले क्यों बोल रहे हैं, हिंदी वाले बोलिए न। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप समझ रहे हो क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आया।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

15. From CAMPA fund 6 thousand 395 narva and about 23 lakh hectare of catchment area has been treated. From the CAMPA fund 66 lakh 56 thousand man days employment has been generated in past 9 months. The 'Hathi-Manav Sangwari Yojana' has increased the hopes of ending elephant menace.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, जिस सरकार को राज्यपाल पद पर विश्वास नहीं है, उसके विरूद्ध वे कोर्ट गये हैं और न्यायालय में केस चल रहा हैं। सरकार के एक्सचेकर से वकीलों को फीस दी जा रही है और फिर राज्यपाल जी से अपना अभिभाषण पढ़वाना इसका औचित्य क्या है ? जब राज्यपाल पद के उपर में विश्वास ही नहीं है तो फिर उनके अभिभाषण का कोई औचित्य ही नहीं है ? (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

16. In the past 4 years, the distribution of individual and community forest resource right letter increased to over 5 lakh 15 lakh thousand and the land allotted under the scheme has increased from 11 lakh hectares to 40 lakh hectares.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- जब अधिकार और दायित्व का निर्धारण हाईकोर्ट कर रही है...। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

17. By returning the land in Lohandiguda, my government has given a message that arrangements would be made for the economic self-reliance of tribal community while keeping them connected with their traditions. 562 food processing units have established in the state.

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े वकील यहां केस लड़ने के लिए आ रहे हैं। हवाई जहाज में स्पेशल फ्लाईट से आ रहे हैं और गवर्नर साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- हवाई जहाज में स्पेशल फ्लाईट से आ रहे हैं। गवर्नर साहब आपको वकील भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आप लोग सब यात्री ट्रेन बंद कर दिए हो, इसलिए हवाई जहाज से आना पड़ रहा है। यात्री ट्रेन से आने वाले अब सुपर फास्ट ट्रेन से आएंगे। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

18. My government has provided financial assistance for the development of Devguri and Gotul, organized 'National Tribal Dance Festival', declared public holiday of 'The International Day of the World's Indigenous people', initiatives like 'Shaheed Veer Narayan Singh Museum' and development of Giroudpuri Dham has taken.

श्री सौरभ सिंह :- गवर्नर साहब ला सब असत्य ला पढ़वात हे इहां अऊ सुप्रीम कोर्ट में केस करत हे। .

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी....।

श्री अजय चंद्राकार :- तोर कल के चलत हे, (व्यवधान) जा वहां धरना दे।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

19. Under 'Chirag project', in 14 tribal-dominated districts efforts are being taken extend the benefits of agriculture and related opportunities to the local people

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, Please silence.

श्री सौरभ सिंह :- Honourable Governor sahab, They are all asking you to tell live and they have produced this chief secretary against you in the court.

श्री रामकुमार यादव :- सौरभ जी, Please silence. (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसे चार लोग हैं, हम लोग तो पढ़े ही नहीं हैं तो क्या बताएंगे। (व्यवधान) श्रीमान आप हिंदी में पढ़ दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- Please don't disturb. Governor speech is continue. listen please.

श्री सौरभ सिंह :- Governor sahab please you have to clearfly why this goverment this against going to the court against this judicial.....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- जब राज्यपाल जी के अधिकार को ही चुनौती दी जा रही है तो इस भाषण का क्या औचित्य है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हो गया, हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार आपके अधिकारों को चुनौती दे रही है तो इस भाषण का औचित्य क्या है ?

माननीय राज्यपाल महोदय :-

20. It was an irony that the tribal society was not getting the benefits of the PESA law for resolving it rules have been formed for the PESA law in the state. The steps taken for their economic and social empowerment has created an environment of trust, this is why Bastar is gaining a new identity of 'Vikasgarh' in place of 'Naxalgarh'.

श्री कुलदीप जुनेजा :- अमरजीत जी, बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी जवाब दे सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैया, तैं तो हिंदी भी नई समझस, अंग्रेजी भी नई समझस। तैं काबर बोलथस। अऊ गुरूमुखी में भाषण होय नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम जिस विषय को उठा रहे हैं, यह संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक प्रमुख को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। (व्यवधान)

माननीय राज्यपाल महोदय :-

21. My government under the 'Rajiv Gandhi Gramin Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Yojana' has provided over Rs. 326 crores to the families in the past years.

श्री अमितेश शुक्ल :- ब्रज भाई, मैं अध्यक्ष जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह गवर्नर के पहले का कुछ मामला होगा और इसको केन्द्र सरकार ने बनाया है, हमने इसको थोड़ी बनाया है, उस पर क्यों आब्जेक्शन कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल पद पर विश्वास नहीं है। उनके भाषण को पढ़ने का औचित्य क्या है ? हम चाहते हैं कि इसके उपर में व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- Please listen.

माननीय राज्यपाल महोदय :-

22. For bringing together the youth power of state, 13 thousand 107 Rajiv Yova Mitan Clubs have been formed.

श्री बृहस्पत सिंह :- बृजमोहन भैया, यह बात आपको मोदी जी को समझाना चाहिए था न कि हिंदी वाला भी दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय बृहस्पत जी, आप समझा दो। रोज धरने में बैठ रहे हो। मुख्यमंत्री जो को आप समझा दो। आप हमको समझाओगे ? आपकी क्या दुर्गति है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। आपको सड़क में बैठना पड़ रहा है। आपकी दुर्गति को पूरे लोग देख रहे हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

23. As a result of the efforts of my government, sports infrastructure development has accelerated in the state and now residential and non-residential sports academies are also functioning.

श्री बृहस्पत सिंह :- इसलिए आप लोग राज्यपाल जी का विरोध कर रहे हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- राज्यपाल जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम सरकार का विरोध कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग राज्यपाल जी के समर्थन में खड़े हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

24. Under Government of India's 'Khelo India Yojana', approval of 14 'Khelo India Laghu Kendra' has been received.

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सरकार ने राज्यपाल जी के अधिकारों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जब आप अधिकारों को चुनौती दे रहे हो तो भाषण क्यों करवा रहे हो।

श्री अमितेश शुक्ल :- भाई, वह पहले का मामला है, आपने बाद में बनाया है, केन्द्र की सरकार ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। हमको इसमें क्या करना है।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

25. For promoting traditional sports, 'Chhattisgarhia Olympics' was organized.

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका नंबर नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर लो। आप अभी यहां हो, अगली बार वहां चले जाओगे। यहां नहीं आओगे, आप चिंता मत करो।

श्री अमितेश शुक्ल :- नहीं-नहीं, आप फालतू बात मत करिए। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- वैसा ही होगा।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आप अपनी चिंता करिए। यह सब बात आपकी पार्टी से ज्यादा आ रही है।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

26. 6 new districts, 19 new sub-divisions and 83 new Tehsils were formed in the last 4 years.

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां आने वाले नहीं हो।

श्री कुलदीप जुनेजा :- छत्तीसगढ़ में ज्यादा वोट से जीते हैं, इस बार उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी से इन लोगों का भरोसा उठ गया है।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

27. Last year 2 thousand 247 km road works were completed. Construction of 41 major bridges has been completed and construction of 159 major bridges is in progress.

28. So far under the 'Pradhan Manrti Gram Sadak Yojana', 40 thousand 222 km long 8 thousand 174 roads and 349 major bridges have been constructed in the state. 'Mukhyamantri Gram Sadak Evam Vikas Yojana', under which construction of 1 thousand 709 roads of length 4 thousand 486 km has been completed.

29. My government has made valiant efforts to connect Chhattisgarh with aviation services from all sides.

30. As a result of better management the acreage of irrigation has gone up to 38.79 percent. (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- ठोको, ताली ठोको। बिना समझे ताली ठोको।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

31. Drinking water is being supplied through over 2 lakh 61 thousand hand pumps. Drinking water is being provided in 45 thousand 844 rural schools, 41 thousand 661 Anganwadi centers, also through 4 thousand 551 Grameen NalJalYojana, 2 thousand 128 Grameen Sthal Jal Praday Yojana, drinking water is being supplied that has made rural life easier to a great extent.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, आप सबको बताइये कि कहां पर ताली बजाना है और कहां पर नहीं बजाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- क्या है कि इस बार वह बगल में बैठे हैं। अब आप ताली बजाएंगे तो सब ताली बजाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है कि कहां ताली बजाना है और कहां नहीं बजाना है तो बाकी सदस्य क्या करे?

माननीय राज्यपाल महोदय :-

32. For ensuring the purity of drinking water and maintaining awareness about the same, 'Jal Bahini' and 'Jal Mitan' training programs are being conducted.

33. My government has implemented the scheme of 'E-category' registration, in which works up to Rs. 20 lakh are being allotted.

34. Examination fee for the local aspirants of the state in recruitment exams conducted by CGPSC and VYAPAM has been waived off. (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- जुनेजा जी, क्या हो गया है?

श्री सौरभ सिंह :- इन्हीं के बारे में कुछ बोल रहे हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

35. For the effective implementation of Chhattisgarh government's asministrative innovations, 'Navachar Aayog' (innovation commission) has been constituted.

36. My government is committed for providing the benefits of reservation in government service and professional course to the members of scheduled caste, scheduled tribe and orher backward classes as per law. (मेजों की थपथपाहट)

37. 'Mukhyamantri Haat-Bazar Clinic Yojana' has benefited about 84 lakh people. Chief Minister Urban Slum Health Scheme has benefited about 40 lakh patients living in urban bodies. More than 1

Lakh 42 thousand women have been treated under the 'Mukhya Mantri Dai-Didi Clinic Scheme'. Under 'Shri Dhanwantri generic medical store scheme', 194 shops are running in urban bodies where medicines are available at a subsidized rate. (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- वैरी गुड।

माननीय राज्यपाल महोदय :-

38. Korba, Mahasamund and Kanker districts have received the gift of new medical colleges. (मेजों की थपथपाहट)

39. My Government has taken result oriented steps through 'Mukhyamantri Suposhan Yojana', as a result the rate of malnutrition in Chhattisgarh has climbed down from the national average.

40. I am happy to say that Chhattisgarh's Swachhta (cleanliness) model has now become country's most famous cleanliness model. Chhattisgarh has received the national tital of second cleanest state in the Swachh Amrit Mahotsav under Swachh Survekshan 2022. In 2019, 2020 and 2021 Chhattisgarh had received the national award for the cleanest state of India. (मेजों की थपथपाहट)

41. My government has removed the ban on he sale and purchase of small plots and simplified the registration process. Similarly, the decisions of 30 percent reduction in market rates, 2 percent discount on residential buildings have benefited the general public. The district collector has been given the authority to allot government land up to 7 thousand 500 square feet.

42. Under Pradhan Mantri Awas Yojna (Rural), construction of 8 lakh 33 thousand 488 housed has been completed.

43. Construction of 1 lakh 9 thousand 80 houses have been completed and construction of over 60 thousand houses under 'Mor Zameen-Mor Makan' and 'Mor Makan-Mor Chinhari' scheme is under progress.

44. Under the 'Tunhar Sarkar Tunhar Duar Yojana', over 16 lakh people were provided RC books and driving licenses on their doorsteps.

45. 'Swami Atmanand Excellent English Medium School Scheme' has been extended to Hindi medium schools and English medium colleges. In this way, 279 Swami Atmanand schools of excellence are functioning.

46. To improve the standard of education in government schools steps have been taken under 'Sughghar Padhwaiya Yojana'.

47. In 2018 a total number of 491 colleges were functioning in the state which has now increased to 549.

48. 'One nation one ration card scheme' is being implemented so that beneficiaries could receive ration from fair price shop located in any state. Presently, 13 thousand 451 fair price shops are operational in the state.

49. For food and nutrition security, 'fortified rice' containing iron and folic acid is being distributed in 10 aspirational districts.

50. In order to provide relief to the ration card holders of the state, 64 lakh Antyodaya, Prathmikta, Ekal Nirashrit and Nihshaktjan ration card holders were provided free rice for 8 months, from April 2022 to December 2022.

51. For the prevention of online gambling, 'Chhattisgarh Gambling Prohibition Bill-2022' has been passed.

52. Faith centers are being developed through projects like the "Ram Van-Gaman Paryatan Paripath". The impressions of Lord Shri Ram and being protected and preserved at 75 places in this circuit.

53. In past four years, more than 42 lakh domestic consumers have received rebate of Rs. 3 thousand 381 crore under the 'Half Bijli Bill Scheme'.

(कंडिका 54 से कंडिका 70 तक पढ़ा हुआ माना गया) [1]

71. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के लिए नई आशा और नए विश्वास का गढ़ बनाने में सफलता हासिल की है । "नवा छत्तीसगढ़" वास्तव में जनहितैषी नीतियों और सशक्त निवासियों का राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ महतारी की संतान के रूप में आम जनता का उसका अधिकार दिलाने की दिशा में विधानसभा सदस्य के रूप में, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है । मुझे खुशी है कि आप सभी माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं । आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई)

(माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया)

समय :

11.35 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है, सचिव, विधान सभा उसकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।[2]

---

[1] परिशिष्ट "एक"

[2] ---"---

समय :

11.36 बजे

<u>माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव</u>

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र के समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं, शुक्रवार दिनांक 03 मार्च तथा 4 मार्च, 2023 की तिथि निर्धारित करता हूं। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं, वे गुरूवार दिनांक 02 मार्च, 2023 के मध्यान्ह 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

समय :

11.37 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए गुरूवार, दिनांक 02 मार्च, 2023 की तिथि निर्धारित करता हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

<u>माननीय मंत्रिगण हेतु नवनिर्मित नवीन भवन कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 के समीप माननीय मंत्रीगणों हेतु नवनिर्मित नवीन भवन कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम आज सोमवार दिनांक 01 मार्च, 2023 को सभा की कार्यवाही स्थगित होने के तुरन्त पश्चात किया जायेगा।

आयोजित कार्यक्रम एवं उसके पश्चात हाई-टी में आप सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण आमंत्रित हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11.38 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

1. वित्तीय कार्य

(1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन बुधवार दिनांक 1 मार्च, 2023 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का उपस्थापन सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2023 को मध्यान्ह 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को होगी।

(3) मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 से बुधवार, 22 मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) गुरूवार, दिनांक 23 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक से सम्बन्धित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	2 घंटे 30 मिनट
(2) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	2 घंटे
(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री	2 घंटे
(4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री	2 घंटे
(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	2 घंटे
(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	2 घंटे
(7) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	2 घंटे
(8) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री	1 घंटा
(9) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	1 घंटा

(10) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री 1 घंटा

(11) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री 1 घंटा

(12) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री 1 घंटा

(13) श्री अमरजीत भगत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 1 घंटा

2. <u>विधायी कार्य</u>

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

पर चर्चा हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 को सभा की बैठक रखी जाकर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तथा दिनांक 13 मार्च, 2023 से 23 मार्च 2023 तक भोजन अवकाश नहीं होगा। साथ ही सभा की कार्यवाही रात्रि 7.00 बजे तक होगी।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अनुमोदन करवाने की क्या जरूरत है, जब सरकार उसके विपरीत काम करती है तो।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 02 मार्च, 2023 के 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 02 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक 01 मार्च, 2023 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

परिशिष्ट "एक"

श्री विश्व भूषण हरिचंदन

माननीय राज्यपाल

छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

छत्तीसगढ़ विधानसभा

का बजट सत्र

रायपुर 01 मार्च, 2023

माननीय सदस्यगण,

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सोलहवां सत्र, फाल्गुन–चैत्र के पावन माह में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त जनादेश से वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ था। मेरी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल का यह पांचवां बजट सत्र है। वर्ष 2023–24 के बजट सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श और निर्णय की कार्यवाही आप लोगों द्वारा की जाएगी। 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' तथा 'सेवा–जतन–सरोकार' के ध्येय वाक्य के साथ जो 'छत्तीसगढ़ मॉडल' की शुरुआत हुई थी, उसे मुकाम तक पहुंचाने में मेरी सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने के लिए, मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

2. किसान, खेती, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का समन्वित और सर्वांगीण विकास मेरी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में प्रचलित परिपाटियों में सुधार के साथ अनेक नए उपाय भी किए गए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के किसान व ग्रामीण परिवार तेजी से समृद्ध और खुशहाल हुए हैं।

3. अपने प्रदेश की माटी को जहरीले रसायनों से मुक्त करने की बड़ी चुनौती मेरी सरकार ने स्वीकार की है ताकि जमीन का उपजाऊपन, फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके लिए विभिन्न तकनीकी उपायों के साथ ही जनभावनाओं के स्तर पर भी पहल की गई और प्रतिवर्ष अक्ति त्यौहार को 'माटी पूजन दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की गई।

4. मेरी सरकार ने 'सुराजी गांव योजना' के माध्यम से 'नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी' के संरक्षण, बहुआयामी विकास और उसके माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाया है। 'नरवा' के उपचार से भूमिगत जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वहीं गौठानों को गौमाता की सेवा के साथ ही जैविक खाद बनाने व अन्य आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया गया है। सतत एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. 'गोधन न्याय योजना' के तहत गोबर खरीदी की मात्रा 100 लाख क्विंटल तथा गोबर खरीदी की राशि 200 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। 28 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी

उपलब्धि है। गौठान समिति के माध्यम से गौ–मूत्र का क्रय भी किया जा रहा है और इससे जैविक कीट नियंत्रक एवं जीवामृत जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। गोधन और गौ–मूत्र के कार्य से पशु पालकों, गौठान समितियों तथा स्व–सहायता समूहों को होने वाली आय 400 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। गौठानों को 'ग्रामीण औद्योगिक पार्क' के रूप में विकसित करने की नई पहल से गांव–गांव में बड़े पैमाने पर अनेक वस्तुओं के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण हेतु 75 गौठानों का चयन कर 84 लोगों को प्रशिक्षण हेतु राजस्थान भेजा गया है। 13 जिलों में 23 पेंट निर्माण इकाई लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें 3 जिलों रायपुर, दुर्ग एवं कांकेर में उत्पादन भी शुरू किया जा चुका है।

6. 5 हजार 874 गौठानों में चारागाह विकसित किए जा चुके हैं, जिसमें 2 लाख 30 हजार क्विंटल हरा चारा का उत्पादन तथा 15 लाख 80 हजार क्विंटल सूखा चारा पैरा इकट्ठा किया जा चुका है जो पैरादान के लिए मेरी सरकार के आह्वान का सुखद परिणाम है।

7. मेरी सरकार ने प्रदेश की प्रमुख फसल धान को भरपूर सम्मान दिया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सटीक व्यवस्था और मिलिंग की सही नीति से राष्ट्रीय स्तर के कीर्तिमान बने हैं। वर्ष 2017–18 में

12 लाख 6 हजार किसानों ने 19 लाख 36 हजार हेक्टेयर रकबे में उपजाया 56 लाख 89 हजार मीटरिक टन धान बेचा था, वहीं मेरी सरकार के विशेष प्रयासों के कारण इस वर्ष 23 लाख 50 हजार किसानों ने 30 लाख 14 हजार हेक्टेयर रकबे में उपजाया 1 करोड़ 7 लाख 53 हजार मीटरिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। इस तरह छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला प्रथम, धान की सर्वाधिक कीमत देने वाला अव्वल और सेंट्रल पूल में चावल देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। धान के साथ ही अन्य फसलों के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

8. प्रदेश में पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली कोदो, कुटकी, रागी लघु धान्य फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर इनका उपार्जन किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 से 'छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन' कार्यक्रम लागू किया गया है। मिलेट्स के उत्पादन, विपणन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने 'छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड' का गठन किया गया है।

9. खाद्यान्न व उद्यानिकी फसलों की लागत में राहत देने हेतु कृषकों को आदान सहायता राशि प्रदान करने वाली 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' मेरी सरकार ने खरीफ वर्ष 2019 से प्रारंभ की। इसके तहत अभी तक 16 हजार 415 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

10. बिना ब्याज के कृषि ऋण प्रदाय योजना के तहत वर्ष 2022–23 के लक्ष्य 6 हजार 610 करोड़ रुपए के विरुद्ध 6 हजार 141 करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया जा चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान है।

11. मेरी सरकार ने किसानों, ग्रामीणों, वन आश्रितों के बैंक खाते में सीधे भुगतान के साथ ही बैंकिंग सुविधाओं में भी आशातीत वृद्धि की है। वर्ष 2018 की स्थिति में 14 लाख 16 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे, जो अब बढ़कर 21 लाख 23 हजार हो गए हैं। नक्सल प्रभावित 8 जिलों में बैंक शाखाएं 338 से बढ़कर 573 हो गई हैं। एटीएम की संख्या 222 से बढ़कर 456 हो गई है। बस्तर और सरगुजा संभाग में सहकारी बैंक की 10 नई शाखाएं संचालित करने हेतु स्वीकृति दी गई है। बैंक मित्रों की संख्या भी दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 35 हजार कर दी गई है। 725 नई प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम–सह

कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 645 के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

12. प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नवीन उद्यानिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। किसानों को आसानी से कृषि यंत्रों की सुविधा दिलाने हेतु 3 हजार 63 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

13. प्रदेश में 5 लाख 91 हजार मीटरिक टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का छठवां बड़ा राज्य बन गया है। जलाशयों में केज कल्चर के द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में राज्य अग्रणी है। प्रदेश के 30 जलाशयों में अब तक 4 हजार 21 केज लगाए गए हैं, जिनसे मछली पालकों को लगभग 80 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति केज आय प्राप्त हो रही है।

14. कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा, साजा, उपमंडी धमधा एवं पाटन की उपमंडियों में एग्री प्लाजा बनाए जा रहे हैं। कृषकों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर, कांकेर एवं धमतरी में कम्युनिटी सीड बैंक की स्थापना की गई है। तमाम प्रयास बताते हैं कि प्रदेश में किसानों व इससे जुड़े काम करने वाले ग्रामीणों का भविष्य उज्ज्वल हो गया है।

15. मेरी सरकार वनों के संरक्षण, संवर्धन के साथ ही इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों को आजीविका के नए–नए साधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा करने से 13 लाख संग्राहकों को प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। प्रोत्साहन राशि के रूप में विगत तीन वर्षों में 340 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लघु वनोपज से आजीविका मजबूत करने की दिशा में बड़ी सोच से काम लिया गया, जिससे 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। इनके प्रसंस्करण और विपणन हेतु भी अनेक उपाय किए गए हैं। 130 से अधिक उत्पादों का प्रसंस्करण कर 'छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड' के नाम पर विक्रय किया जा रहा है।

16. प्रदेश में हरित आवरण की सुरक्षा के लिए विगत एक वर्ष में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक पौधों का रोपण, 1 करोड़ 33 लाख से अधिक पौधों का वितरण तथा नदी तटों पर 15 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाना अपने आप में बड़ी पहल है। वृक्षारोपण के साथ आजीविका को जोड़ने हेतु 'मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना' शुरू की गई है, जिससे किसानों की निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों का

रोपण कराया जाएगा। कुल पांच वर्षों में 1 लाख 80 हजार एकड़ में 15 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है, जिसके परिपक्व होने से हितग्राहियों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है।

17. कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में 6 हजार 395 नरवा एवं लगभग 23 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र को उपचारित किया गया है। कैम्पा मद से 66 लाख 56 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन इसी वित्तीय वर्ष के 9 माह में किया जा चुका है, जो वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वन्यप्राणियों के संरक्षण और उनके रहवास में सुधार की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 'हाथी–मानव संगवारी योजना' से हाथियों के उत्पात से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बाघ, मगरमच्छ, कृष्णमृग, पहाड़ी मैना, गिद्ध आदि के संरक्षण हेतु विशेष कार्ययोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

18. मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अन्य परंपरागत वन निवासियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के वैधानिक अधिकारों को लेकर विशेष संवेदनशीलता दिखाई है ताकि ऐसे सभी समाज सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ राज्य के विकास में भागीदार बन सकें। विगत 4 वर्षों में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन

संसाधन अधिकार पत्रों के वितरण में तेजी लाई गई तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की शुरुआत भी की गई, जिसके कारण कुल वन अधिकार पत्रों की संख्या बढ़कर 5 लाख 15 हजार से अधिक हो गई तथा इसके तहत आवंटित भूमि 11 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी धमतरी जिले से की गई है।

19. मेरी सरकार ने लोहंडीगुड़ा में जमीन वापस करने के साथ यह संदेश दिया था कि आदिवासी समाज को उनकी परंपरा से जोड़े रखते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन की व्यवस्था की जाएगी। इस दिशा में तेजी से प्रगति करते हुए 50 से अधिक वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए। फूडपार्कों की स्थापना के लिए मात्र चार वर्षों में 112 विकासखंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकासखंडों में भूमि हस्तांतरण किया जा चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित की जा चुकी हैं।

20. मेरी सरकार ने नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक ओर जहां देवगुड़ी तथा गोटुल के विकास हेतु आर्थिक सहायता दी है, 'राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव' का आयोजन,

'विश्व आदिवासी दिवस' पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, 'शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय' तथा गिरौदपुरी धाम के विकास जैसी पहल की है, वहीं दूसरी ओर नए जमाने की शिक्षा से सक्षम बनाने के लिए 'आदर्श छात्रावास योजना', 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना', 'शिष्यवृत्ति योजना', 'छात्र भोजन सहाय योजना', 'राजीव युवा उत्थान योजना', 'राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना', 'जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना' जैसी योजनाओं के बेहतर संचालन की व्यवस्था की है और इनसे मिलने वाले लाभ को भी बढ़ाया है।

21. विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया है। वहीं 'चिराग परियोजना' के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि एवं इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है।

22. पेसा कानून का लाभ आदिवासी समाज को न मिल पाना एक विडम्बना थी, जिसका समाधान करते हुए प्रदेश में पेसा कानून के लिए नियम बनाए गए। मेरी सरकार ने न्याय की अवधारणा को व्यापक विस्तार देते हुए जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझे

आदिवासियों की रिहाई सुनिश्चित की। उनके आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों से विश्वास का वातावरण बना, जिसके कारण दुर्गम अंचलों में भी सड़क निर्माण, बिजली प्रदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पानी, पोषण, रोजगार, 'बस्तर फाइटर्स' बल में भर्ती जैसे अनेक उपाय किए जा सके हैं। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि 'विकासगढ़' के रूप में नई पहचान पा रहा है। इस तरह नक्सलवादी तत्वों को कमजोर करते हुए लोगों की अपने गांवों में वापसी सुनिश्चित की गई।

23. मेरी सरकार ने 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के अंतर्गत आर्थिक रूप से सर्वाधिक कमजोर तबकों ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी–पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्रों के बैगा, गुनिया, मांझी, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मुहारिया आदि को सालाना 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की पहल की है। विगत वर्षों में इन परिवारों को 326 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

24. प्रदेश के कुल 26 लाख 70 हजार 308 गरीब परिवारों की महिलाओं को 2 लाख 48 हजार 134 स्व–सहायता समूहों से जोड़ा गया है तथा गठित स्व–सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु कुल 13 हजार 954 ग्राम संगठन एवं 568 संकुल स्तरीय संगठन संचालित हैं।

25. विभिन्न तरह के कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु मेरी सरकार द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा पूर्व योजनाओं में सुधार करते हुए उससे जरूरतमंदों को अधिक लाभ दिलाने का काम भी किया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना', 'मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षण–प्रशिक्षण सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री नोनी–बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना' तथा 'निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना' इस प्रसंग में नए उदाहरण बने हैं।

26. प्रदेश की युवा शक्ति को संगठित करने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां आयोजित कराने तथा सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए अब तक 13 हजार 107 राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जा चुका है। इन क्लबों से युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने का उचित मंच तथा सुविधाएं मिली हैं।

27. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास में तेजी आई है और अब आवासीय तथा गैर आवासीय खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है। राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई–बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स की आवासीय अकादमी संचालित है, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक्सीलेंस सेंटर की मान्यता दी गई है। रायपुर में आवासीय तीरंदाजी अकादमी का संचालन किया जा रहा है। हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल एवं एथलेटिक्स की गैर आवासीय खेल अकादमियां रायपुर में तथा तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेन्द्र शिवतराई–बिलासपुर में संचालित है।

28. भारत सरकार की 'खेलो इंडिया योजना' के तहत प्रदेश में 14 'खेलो इंडिया लघु केन्द्र' की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें शिवतराई –बिलासपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, नारायणपुर, सरगुजा एवं जशपुर में लघु केन्द्र स्थापित कर, खेल प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है।

29. प्रदेश में पहली बार पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन किया गया। इससे ग्राम, वार्ड से लेकर जिला/संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें हर आयु, हर वर्ग के लोगों की उत्साहजनक भूमिका रही। युवाओं से लेकर

बुजुर्ग माताओं तक की ऊर्जा देखने लायक थी। इससे खिलाड़ी भावना के साथ एकता और समरसता की भावना मजबूत हुई।

30. मेरी सरकार ने अधोसंरचना विकास के काम को आम जनता की सहूलियत से जोड़कर किया। यही वजह है कि प्रशासनिक अधोसंरचना के विस्तार और विकेन्द्रीकरण के लिए विगत 4 वर्षों में 6 नए जिले, 19 नए अनुविभाग और 83 नई तहसीलों का गठन किया गया।

31. सड़क अधोसंरचना के विकास हेतु बहुस्तरीय प्रयास किए गए। राज्य मद के अंतर्गत विगत वर्ष में 2 हजार 247 किलोमीटर सड़क कार्य पूर्ण किए गए। 41 वृहद पुल निर्माण पूर्ण किया गया तथा 159 वृहद पुल निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 10 रेलवे ओव्हर ब्रिज तथा अण्डर ब्रिज के कार्य पूर्ण किए गए हैं। 'जवाहर सेतु योजना' के तहत अभी तक 36 पुल निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 56 पुलों के कार्य प्रगति पर हैं। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा अभी तक 568 किलोमीटर लंबी 95 सड़कों तथा 3 पुलों के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

32. एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की तृतीय ऋण परियोजना अंतर्गत 826 किलोमीटर लंबी 3 हजार 370 करोड़ रुपए लागत की सड़कों का कार्य प्रगति पर है। ए.डी.बी. चतुर्थ ऋण परियोजना अंतर्गत 539 किलोमीटर लंबी सड़कों का चयन किया गया है।

33. केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) योजना के तहत 2 कार्य पूर्ण हुए एवं 16 कार्य प्रगति पर है। आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजना के तहत 204 कार्य पूर्ण हुए एवं 102 कार्य प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 किलोमीटर कॉरीडोर योजना अंतर्गत 14 किलोमीटर एवं एन.एच.डी.पी. योजना में 6 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया गया है। इसी के साथ 11 पुल कार्य भी प्रगति पर हैं।

34. 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 40 हजार 222 किलोमीटर लंबी 8 हजार 174 सड़कें तथा 349 बड़े पुलों का निर्माण किया जा चुका है। जिन सड़कों की संधारण अवधि 5 वर्ष हो चुकी है, वैसी 22 हजार 637 सड़कों की मरम्मत और 3 हजार 201 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्ड में नहीं आतीं, उनके लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना' मेरी सरकार ने लागू की है, जिसके अंतर्गत 4 हजार 786 किलोमीटर लंबी 1 हजार 709 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 'मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना' के अंतर्गत भी 2 हजार 155 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

35. छत्तीसगढ़ को सभी ओर से विमानन सेवाओं से जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए, जिसके कारण जगदलपुर से विमान सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं, साथ ही जगदलपुर को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिलासपुर को तीन राज्यों से जोड़ा जा चुका है, और अब नाइट लैंडिंग की सुविधा विकसित की जा रही है। अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर और कोरबा में भी हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है।

36. प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि को मेरी सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें एक ओर परंपरागत उपायों को अपनाया गया है, वहीं दूसरी ओर जल संसाधन के विकास पर भी जोर दिया गया है। यही वजह है कि प्रदेश में राज्य गठन के समय जो निर्मित सिंचाई क्षमता 13 लाख 28 हजार हेक्टेयर थी, वह अब बढ़कर 21 लाख 49 हजार हेक्टेयर हो गई है। सिंचाई का रकबा 38.79 प्रतिशत हो गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि बेहतर प्रबंधन से विगत वर्ष में जो खरीफ सिंचाई 12 लाख 86 हजार हेक्टेयर में की गई थी, वह इस वर्ष बढ़कर 13 लाख 5 हजार हेक्टेयर हो गई है, अर्थात एक वर्ष में वास्तविक सिंचाई क्षमता में 19 हजार हेक्टेयर की वृद्धि अपने आप में उत्साहजनक है।

37. मेरी सरकार ने विभिन्न जरूरतों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में प्रदेश में मात्र 3 लाख 85 हजार घरेलू नल कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गए हैं। सभी बसाहटों में कम से कम एक स्रोत के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 2 लाख 61 हजार से अधिक हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 45 हजार 844 ग्रामीण शालाओं, 41 हजार 661 आंगनवाड़ी केन्द्रों, 4 हजार 551 ग्रामीण नल जल योजनाओं, 2 हजार 128 ग्रामीण स्थल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जन–जीवन बहुत हद तक आसान हुआ है। वन अंचलों तथा कुछ मैदानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिससे 1 लाख 91 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है। 133 शहरी जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर संचालित हैं तथा ऐसी 32 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

38. पेयजल की शुद्धता और इसके बारे में जागरुकता बनाए रखने के लिए 'जल बहिनी' तथा 'जल मितान' के नाम से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आर्सेनिक,

खारे पानी और फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित 201 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

39. मेरी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव उपाय किए हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़, देश में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर है।

40. निर्माण कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 'ई–श्रेणी' में पंजीयन की योजना लागू की है, जिसमें 20 लाख रुपए तक के कार्य आवंटित किए जा रहे हैं, 6 हजार से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन कर, 337 करोड़ रुपए के कार्य आवंटित किए गए हैं।

41. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ किया गया है। इससे अधिक संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।

42. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर राज्य शासन को सुझाव देने के उद्देश्य से 'नवाचार

आयोग' का गठन किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ में नवाचार को बढ़ावा देने एवं पूर्व से राज्य में प्रचलित नवाचार की प्रथाओं में निरंतरता बनाए रखने से कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।

43. मेरी सरकार आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधि अनुसार आरक्षण का लाभ देने हेतु कटिबद्ध है। इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया है, जो अभी अनुमति हेतु विचाराधीन है।

44. विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को उनकी अर्हता अनुसार उनके जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने व शासकीय सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है।

45. मेरी सरकार ने हर आपदा को सेवा के अवसर के रूप में देखा है। यही वजह है कि कोरोना काल हो, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक प्रकोप हो, दुर्घटना हो या वन्यप्राणियों से लोगों को हुई क्षति हो, ऐसे हर अवसर पर प्रभावितों को सहानुभूतिपूर्वक समुचित मदद की गई है। इतना ही नहीं, युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे राज्य के 183 नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी हेतु निकटतम एयरपोर्ट तक हवाई यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन द्वारा की गई है।

46. मेरी सरकार ने जन–स्वास्थ्य के लिए एक ओर जहां अस्पतालों को नई–नई सुविधाओं से सुसज्जित किया, चिकित्सा शिक्षा के साथ मेडिकल कॉलेज स्तर की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं को जन–जन तक पहुंचाने के नए–नए उपाय भी किए। यही वजह है कि प्रदेश में मलेरिया तथा अन्य महामारियों पर प्रभावी अंकुश लगा है।

47. 'मुख्यमंत्री हाट–बाजार क्लीनिक योजना' से लगभग 84 लाख लोगों को लाभ मिला है। 'मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना' से नगरीय निकायों के लगभग 40 लाख मरीजों को लाभ मिला है। 'मुख्यमंत्री दाई–दीदी क्लीनिक योजना' से 1 लाख 42 हजार से अधिक माताओं एवं बहनों का उपचार हुआ है। 'श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल

स्टोर योजना' के तहत नगरीय निकायों में 194 दुकानें संचालित की जा रही हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक की रियायती दर पर दवाएं दी जा रही हैं। इस योजना से 44 लाख से अधिक लोगों को लगभग 82 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

48. मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा देने के लिए 'डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना', 'हमर लैब योजना' जैसी पहल से लोग खर्च की चिंता छोड़कर सही उपचार के लिए आगे आ रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ लगभग 40 लाख लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा 'शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण', 'डायलिसिस कार्यक्रम दीर्घायु वार्ड', 'आयुष स्वास्थ्य सेवाएं' आदि उपायों का भी लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मेरी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जन–विश्वास बढ़ने के कारण प्रदेश की मातृ मृत्युदर 379 से घटकर 137 हो गई है। वहीं संस्थागत प्रसव में भी लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि होना सुखद संकेत है।

49. यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के कोरबा, महासमुन्द व कांकेर को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, वहीं दुर्ग जिले के चंदूलाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय को सरकार द्वारा अधिग्रहित

करने से शासकीय चिकित्सा शिक्षा व उपचार का दायरा तेजी से बढ़ा है।

50. महिलाओं और बच्चों की उचित देखभाल और स्वस्थ विकास में पोषण की बड़ी भूमिका होती है। मेरी सरकार ने 'मुख्यमंत्री सुपोषण योजना' के माध्यम से परिणाममूलक कदम उठाए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। इस दौरान 2 लाख 65 हजार बच्चों को कुपोषणमुक्त किया गया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्यौहार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, पूरक पोषण आहार, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना, सखी वन स्टाप सेंटर, शक्ति सदन योजना, सखी निवास योजना, नवा बिहान योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, सक्षम योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन वात्सल्य, उजियार योजना, छत्तीसगढ़ बाल कोष, बाल सक्षम नीति आदि से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है तथा नौनिहालों की बुनियाद मजबूत की जा रही है।

51. मेरी सरकार ने व्यापक पारदर्शिता के साथ नागरिक सेवाओं के विस्तार हेतु न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि घर पहुंच सेवाओं पर भी जोर दिया है। 14 नगर निगमों में 'मुख्यमंत्री मितान योजना' के माध्यम से

लाभान्वित लोगों की संख्या 50 हजार से अधिक हो चुकी है, जिन्हें घर पर सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने का सुख मिला है। आम नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निपटारा टोल फ्री नम्बर 1100 से किया जा रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। 'ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम' के माध्यम से 500 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लाट पर भवन निर्माण की अनुज्ञा ऑनलाइन दी जा रही है।

52. ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए लोक सेवा केन्द्रों को सशक्त बनाया गया, जिसके माध्यम से विगत 4 वर्षों में 1 करोड़ 14 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों की जनहितकारी योजनाओं में भी ऑनलाइन आवेदन और निराकरण का विकल्प दिया गया है, जिससे पारदर्शी और कारगर प्रशासन सुनिश्चित किया जा चुका है।

53. नागरिक सुविधाओं में स्वच्छता का अहम स्थान है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ का स्वच्छता मॉडल अब देश का सबसे प्रख्यात स्वच्छता मॉडल बन गया है, जिस पर हर छत्तीसगढ़वासी को गर्व है। यह गौरव का विषय है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु द्वितीय स्वच्छतम राज्य

का राष्ट्रीय खिताब छत्तीसगढ़ को मिला है। वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में भी छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

54. मेरी सरकार ने राज्य की स्वच्छता की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके लिए 'नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी' योजना से स्वच्छता को जोड़ा गया। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जोर दिया। दोना–पत्तल की परंपरा व बर्तन बैंकों की सुविधा शुरू की, जिससे लोगों का प्लास्टिक के प्रति रुझान कम हो रहा है।

55. मेरी सरकार ने छोटे भूखंडों की खरीदी–बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया तथा पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण किया, जिसके कारण विगत 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक छोटे भूखंडों का क्रय–विक्रय हुआ और इससे मध्यमवर्गीय परिवारों के जीवन में आई आर्थिक रुकावट समाप्त हुई। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया गया। इसी प्रकार बाजार मूल्य दरों में 30 प्रतिशत कमी, आवासीय भवनों पर 2 प्रतिशत छूट जैसे फैसलों का बहुत लाभ आम जनता को मिला। नामांतरण जैसे जरूरी राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और सरलता लाई गई। 7 हजार 500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन

का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। नगरीय क्षेत्र में पट्टे की भूमि पर भू–स्वामी हक देने की पहल की गई है। राजस्व अभिलेखों की शुद्धता एवं विवादित प्रकरणों के स्थायी हल हेतु पूरे राज्य में पुनः सर्वेक्षण का निर्णय भी लिया गया है। इस तरह प्रदेश की जनता को राजस्व मामलों के तनाव से मुक्ति देने की दिशा में अनेक सार्थक कार्य किए गए हैं।

56. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 8 लाख 33 हजार 488 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा इस वर्ष राज्यांश के रूप में 676 करोड़ रुपए की राशि आहरित की चुकी है, जिससे शेष 1 लाख 5 हजार आवास बनाने का कार्य पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके।

57. सभी शहरों को झुग्गीमुक्त करते हुए गरीबों को बेहतर आवास दिलाने की दिशा में 'मोर जमीन–मोर मकान' एवं 'मोर मकान–मोर चिन्हारी' योजनाओं के तहत 1 लाख 9 हजार 80 आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ तथा 60 हजार से अधिक आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए, शहरी किरायेदारों को भी मकान उपलब्ध कराने का प्रयास मेरी सरकार कर रही है।

58. मेरी सरकार ने प्रदेश में परिवहन संबंधित जनसुविधाओं के क्षेत्र में अनेक नए कार्य किए हैं। लोगों को उनके निकट परिवहन संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 368 परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जा चुके हैं। बसों के परमिट ऑनलाइन देने की व्यवस्था की गई है। 'तुंहर सरकार तुंहर दुआर योजना' के अंतर्गत 16 लाख से अधिक लोगों को आरसी बुक तथा ड्राइविंग लायसेंस घर पहुंचाकर दिया गया। लंबित वाहन कर की वसूली हेतु 'एकमुश्त निपटान योजना' लागू की गई। नीतिगत पहल के तहत मेरी सरकार ने जो नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022' लागू की थी, उसके तहत पंजीकृत वाहनों को सब्सिडी का भुगतान भी किया जा रहा है।

59. शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने बड़े सुधार किए हैं। 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना' से शुरू की गई पहल को विस्तार देते हुए हिन्दी माध्यम स्कूलों और अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों तक पहुंचाया गया है। इस तरह प्रदेश में 279 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से 2 लाख 15 हजार से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अधोसंरचना प्राप्त हो चुकी है। मेरी सरकार आगामी सत्र से 398 ऐसे नए विद्यालय शुरू करने की तैयारी भी कर रही है।

60. 'सुघ्घर पढ़वइया योजना' के माध्यम से भी शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु कदम बढ़ाए गए हैं। मेरी सरकार ने राज्यव्यापी भाषाई सर्वे के माध्यम से पहली कक्षा के बच्चों को उनके घर में बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाई शुरू कराने का सफल प्रयोग कर देश में अपनी प्रथम पहल को अंजाम दिया है। बस्तर में 200 से अधिक प्राथमिक शालाओं में मातृभाषा में पढ़ाई और गांव–गांव में कहानी–उत्सव के माध्यम से प्रेरक वातावरण बनाया गया है। स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार के लिए 780 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत और जीर्णोद्धार का अभियान शुरू किया गया है। दिव्यांग बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने हेतु 'आईसीटी योजना' से जोड़ा गया है। वहीं दृष्टिबाधित बच्चों को स्मार्ट फोन के साथ 'की–बोर्ड' का प्रशिक्षण देने वाला प्रथम राज्य बनने का गौरव भी छत्तीसगढ़ को मिला है।

61. मेरी सरकार ने युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा दिलाने हेतु व्यापक व्यवस्था की है। वर्ष 2018 में प्रदेश में 491 महाविद्यालय संचालित थे, जो अब बढ़कर 549 हो गए हैं। इनमें प्रवेशित छात्रों की संख्या 2 लाख 66 हजार से बढ़कर 3 लाख 35 हजार हो गई है। पहले मात्र 58 शासकीय महाविद्यालय नैक मूल्यांकित थे, जो

अब बढ़कर 175 हो गए हैं। इस तरह उच्च शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के सुधार किए गए हैं।

62. सार्वभौम पीडीएस जरूरतमंद लोगों का एक बड़ा सपना था, जिसे मेरी सरकार ने साकार किया। किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकें, इस हेतु 'वन नेशन वन राशनकार्ड योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 13 हजार 519 उचित मूल्य दुकानों में से 13 हजार 451 उचित मूल्य दुकानों में ई–पॉस मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

63. खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पोषण सुरक्षा के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड युक्त 'फोर्टिफाइड चावल' का वितरण वर्तमान में प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों, 2 हाई बर्डन जिलों, मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु सभी जिलों में किया जा रहा है। इसका वितरण अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के गरीब राशनकार्डधारियों को प्रारंभ किए जाने का निर्णय स्वागतेय है।

64. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के राशनकार्डधारियों को राहत देने हेतु 64 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन

राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक 8 माह तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया तथा इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। पीडीएस अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण व अन्य उपायों से प्रदेश में पीडीएस का कव्हरेज निरंतर बढ़ा है तथा वर्तमान में इससे लाभान्वित हितग्राही सदस्यों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 61 लाख हो गई है जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100 प्रतिशत कव्हरेज है।

65. मेरी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अपराधियों के लिए कठोर और आम नागरिकों के लिए संवेदनशील बनाया। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बहुत आगे है। विगत चार वर्षों में 460 प्रकरण पंजीबद्ध कर 655 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 43 हजार 945 निवेशकों को लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए 'छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक–2022' पारित किया गया है।

66. मेरी सरकार ने मूल संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करते हुए ऐसे उपाय किए हैं कि उन पर न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी गौरवान्वित हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी माटी के रंग में रंगना आसान हो जाए। विभिन्न अंचलों के पर्वों, त्यौहारों, धरोहरों को संजोया जा रहा है। ग्रामीण परंपराओं तथा कौशल का विकास कर विभिन्न उत्पाद तैयार करने में मदद की जा रही है, जिससे परंपरा को आजीविका के साथ जोड़ने में व आर्थिक स्वावलंबन में मदद मिल रही है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ जैसी परियोजना से आस्था केन्द्रों का विकास भी किया जा रहा है। इस परिपथ में 75 स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चिन्हारी को चिरस्थायी बनाया जा रहा है।

67. मेरी सरकार ने राज्य के संसाधनों और अवसरों को औद्योगिक विकास का मूलमंत्र बनाया। स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम की पुरानी ताकत को मजबूत करते हुए खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज, जूट, दवा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन सेवा केन्द्र, बीपीओ, थ्रीडी प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केन्द्र, बीज ग्रेडिंग आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए आकर्षक पैकेज दिए, जिसके कारण विगत चार वर्षों में प्रदेश में एक हजार 856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनमें 19 हजार 700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ।

68. मेरी सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली से खनिज राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नए खनिजों की खोज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिनके खनन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डीएमएफ के कार्यों की स्वीकृति और भुगतान डीएमएफ पोर्टल से किया जा रहा है तथा संपादित कार्यों का लेखा परीक्षण महालेखाकार से कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

69. ऊर्जा क्षेत्र की बिखरती शक्ति को कुशल प्रबंधन से समेटने में मिली कामयाबी का लाभ मेरी सरकार ने जनता को दिया। इस तरह विगत चार वर्षों में 42 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को 'हाफ बिजली बिल योजना' के माध्यम से 3 हजार 381 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। 16 लाख 72 हजार बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को सिंचाई हेतु पूर्णतया निःशुल्क बिजली दी जा रही है। वहीं अन्य 6 लाख 22 हजार किसानों को 5 हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों में निर्धारित छूट दी जा रही है।

70. विद्युत के पारेषण और वितरण में बड़े पैमाने पर निवेश का लाभ भी जनता को दिया जा रहा है। विगत चार वर्षों में 85 हजार 519 स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन, 4 हजार 724 मजरों–टोलों का विद्युतीकरण,

72 हजार से अधिक सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए के निवेश से विद्युत आपूर्ति में सुधार से लोगों के जीवन स्तर व आजीविका में सुधार हुआ है।

71. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के लिए नई आशा और नए विश्वास का गढ़ बनाने में सफलता हासिल की है। नवा छत्तीसगढ़ वास्तव में जनहितैषी नीतियों और सशक्त निवासियों का राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ महतारी की संतान के रूप में आम जनता को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में विधानसभा सदस्य के रूप में, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप सभी माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़